handed over to Pakistan's High Commission in India on 24th January, 1994;

(c) what are the details of the proposals made to Pakistan;

(d) whether India has totally rejected holding a plebiscite in Jamnui and Kashmir; and

(e) what is the reaction of the Pakistani Government and by when further talks between the two countries will be held?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH): (a) to (c) On 24th January, 1994, six non-papers relating to Siachen, Sir Creek, Tulbal Navigation Project, maintenance of peace and tranquility along the LOC, additional Confidence Building Measures and the India-Pakistan Joint Commission were handed over to Pakistan.

Government have made specific and constructive suggestions on these subjects with the aim to resolving differences with Pakistan peacefully and through bilateral negotiations as well as to move forward in the overall process of the normalisation of relations in accordance with the Simla Agreement.

(d) Yes, Sir.

(e) Pakistan has conveyed on 19th February, 1994 it comments and counter-proposals to the suggestions contained in the six Indian non-papers. These comments and counter-proposals are presently under consideration with the Government.

Government have expressed its readiness for further talks, Pakistan, however, is attempting to like the scheduling of future talks with the ground situation in J & K, including the level of security forces deployed against terrorists in J & K and discussions on the modalities of a plebiscite which Government have consistently regarded as unacceptable.

भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया जाना

*30. **श्री मूल चंद मीणा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को न्यायाधीशों, वकीलों, समाजशास्त्रियों और महिला संगठनों से ऐसे सुझाव और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों में और कठोर दंड दिए जाने का उपबंध करने हेतु भारतीय दंड संहिता में संशोधन किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्री (श्री एस॰ बी॰ चव्हाण): (क) से (ग) बलात्कार सहित हिंसा के बारे में समाचार माध्यमों की रिपोर्टों के संबंध में, अपराधों के लिए सख्त दंड देने सहित कानूनों में संशोधन करने के सुझाव विभिन्न मंचों पर समय-समय पर दिए गए। राष्ट्रीय महिला आयोग, (रा॰म॰आ॰) जिसे महिला राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित मौजूदा नियमों की पर्याप्तता की समय-समय पर पुनरीक्षा करने और उनमें संशोधन का सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, ने अक्तूबर, 1992 में बच्चों के साथ होने वाले बलात्कार पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की थी। इस कार्यशाला में महिला राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रख्यात वकीलों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आयोग से, कार्यशाला में किए गए सुझावों पर विचार करने और इस मामले में अपनी औपचारिक सिफारिशें सरकार को भेजने का अनुरोध किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फलों का व्यापार

*31. **डा॰ जितेन्द्र कुमार जैन:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत विश्व में फलों के मामले में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश है और विश्व-भर में होने वाले फलों के कुल उत्पादन में भारत का योगदान 7.7 प्रतिशत है;

(ख) क्या भारी मात्रा में फलों का उत्पादन होने के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में फलों के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 0.50 प्रतिशत ही है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या यह सच है कि देश में उत्पन्न किये जाने वाले फलों का बहुत बड़ा भाग बिना उपयोग किए ही नष्ट हो जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार देश को प्रतिवर्ष कुल कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(च) क्या सरकार ने इस हानि को कम करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं; यदि हां, तो ये लक्ष्य क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) से (च) एफ ए ओ ईयर बुक 1992 के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है जिसका कुल फल उत्पादन 30 मिलियन टन है। विश्व का अनुमानित फल उत्पादन 370 मिलियन टन है।

कोई सरकारी आकलन उपलब्ध नहीं है किन्तु विश्व के व्यापार में भारत का हिस्सा 0.5 प्रतिशत से कम होने का अनुमान है।

यद्यपि उपयोग के बिना फलों के खराब होने का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है किन्तु यह अनुमान है कि अपर्याप्त फसलोत्तर बुनियादी ढांचे और उत्पाद में खराबी आने के कारण फलों और सब्जियों की गुणवत्ता में खराबी और कीमतों का नुकसान करीब 25 से 30 प्रतिशत तक होता है। परन्तु फलों की पर्याप्त मात्रा का उपयोग परिरक्षण आदि के लिए घरेलू और असंगठित क्षेत्र में किया जाता है अतः उपयोग में न लायी गयी निबल मात्रा 5% से अधिक नहीं होगी।

नुकसान को कम करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये हैं लेकिन यह अनुमान है कि फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापित क्षमता आठवीं योजना के आरंभ में 9.5 लाख टन से बढ़कर योजना के अंतिम वर्ष में 20 लाख टन हो जायेगी। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन और सहायता देने के अलावा सरकार फलों और सब्जियों के लिए विभिन्न फसलोत्तर प्रसंस्करण और संचालन सुविधाएं स्थापित करने के वास्ते भी सहायता और प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इन उपायों से नुकसान में काफी कमी आने की आशा है।

Negotiations on Transit Facilities between India and Bangladesh

32. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is an ongoing negotiation between India and Bangladesh on transit facilities;

(b) if so, what is the extent of the proposed transit facilities;

(c) whether there has been any proposal to include army movement in the proposed transit facilities; and

(d) what has been the progress in the negotiations?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH): (a) Government of India have been interested in securing transit facilities through the Bangladesh territory and have taken up the matter on a number of occasions, at various levels, with the Government of Bangladesh.

(b) Government of India have proposed various modes of transit arrangements to the Government of Bangladesh such as road, railways and using Chittagong harbour as a part of multimodal transit facilities.

(c) No, Sir.

(d) The Government of Bangladesh, so far, have not reacted positively to our proposals.

Shifting of Villages of Uri-Kupwara sector on Border of Kashmir

*33. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of HOME AFFAIRS to pleased to state:

(a) whether Government have received a proposal from the border security force to shift some 40 villages on the border of Kashmir in the Uri-Kupwara sector and